

इज़रायल का ‘‘आयरन डोम’’ डिफेंस सिस्टम ईरान के ‘‘मल्टीलेयर्ड’’ हवाई हमलों के सामने असफल रहा

‘‘आयरन डोम’’ की इस पराजय से भारत में अचानक ‘‘खतरे की घंटियाँ’’ बज उठीं

-सुकुमार साह-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 16 जून। ईरान द्वारा आयरन डोम में सेंघ लगाना इस इज़राइली रक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता और मजबूती पर गंभीर सवाल खड़े करता है, विशेष रूप से ऐसी स्थिति में, जब उस पर तकनीकी रूप से सक्षम और समन्वित हमले किए जाएं। यह पहला अवसर था, जब आयरन डोम स्पष्ट रूप से व्याकुल सा नज़र आया। ईरान का सही तालमेल से किया गया हमला, जिसमें बैलिस्टिक मिसाइलें, क्रूज़ मिसाइलें और डोन शामिल थे, इसके लेयर्ड डिफेंस को चकमा देकर तेल अवीव के किरिया कंपाउंड सहित, कई शहरी और सैन्य लक्ष्यों को निशाना बनाने में सफल रहे।

कई सैन्य विश्लेषकों ने इस क्षण को एक ‘‘रणनीतिक परिवर्तन बिंदु’’ कहा है, अर्थात् वह समय, जब किसी सिस्टम या संगठन को ऐसे बदलाव का सामना करना पड़े, जो उसके भविष्य की दिशा व सफलता को प्रभावित कर दे। पर इसका मतलब यह नहीं कि आयरन डोम पूरी तरह विफल हो गया,

■ भारत ने सदा इज़रायल के ‘‘आयरन डोम’’ सिस्टम पर पूरा भरोसा कर, इस सिस्टम के कई अवतार, जैसे, बराक सरफेस-टू-एयर मिसाइल सिस्टम, स्पाइडर एयर डिफेंस सिस्टम, आदि, खरीदे थे तथा शत्रु देश के हवाई हमले को घंटिया मानते हुए चैन की नींद सो रहा था।

■ ‘‘आयरन डोम’’ में छेद होने से यह भी साबित हुआ कि किसी भी ‘‘डिफेंस सिस्टम’’ पर पूरा भरोसा करके निश्चित हो जाना, कोई अक्लमंदी का काम नहीं है।

■ प्रभावशाली सुरक्षा के लिए आयातित डिफेंस सिस्टम, (जैसे आयरन डोम) चाहे कहीं से, विदेश से, इज़रायल, अमेरिका, रूस आदि से आयातित हो, उसका स्वदेशी ‘‘आर.एण्ड डी.’’ तैपन सिस्टम से समन्वय होना जरूरी है। उदाहरण के लिए, डी.आर.डी.ओ. द्वारा भारत में विकसित आकाश व क्यू.आर.एस.ए.एम. डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान के हवाई हमले, जिसमें लड़ाकू विमान व ड्रोन भारी संख्या में शामिल थे, को नाकाम किया था।

■ निरंतर आर.एण्ड डी. ही भारत को कुछ सुरक्षा प्रदान कर सकती है।

इसने अब भी बड़ी संख्या में हमलों को विफल किया, लेकिन इसकी एक प्रमुख

कमजोरी उजागर हो गई है, वो यह कि यह प्रणाली मूलतः छोटी रेंज के, कम मात्रा में होने वाले रॉकेट हमलों से निपटने के लिए बनाई गई थी, जो कि हमला और हिज्रुल्लाह द्वारा किये जाते हैं, न कि ईरान जैसे बड़े राष्ट्र द्वारा किए जा रहे उच्च मात्रा और बहु-दिशात्मक हमलों से।

भारत, ने इज़राइल से कई रक्षा प्रणालियाँ, जैसे सतह से हवा में मार करने वाली, मिसाइल प्रणाली बराक, एयर डिफेंस सिस्टम स्पायडर, हेरोन यूएवी, हारोप लुटेरिंग म्युनिशन और फाल्कन एडव्यूसीएस खरीदी हैं, यह एक गंभीर पुनर्मूल्यांकन की आवश्यकता पैदा करता है। भारत के समक्ष भी इज़राइल की तरह जटिल सुरक्षा खतरे हैं, जिनमें परमाणु संपन्न पड़ोसी चीन और पाकिस्तान तथा कई अतिवादी समूह शामिल हैं। यह सेंघ दर्शाती है कि इज़राइली प्रणालियाँ, भले ही ‘‘एंसिमेट्रिकल’’ (असंयमित या असंतुलित) युद्ध में प्रभावी रही हों, परंतु तकनीकी रूप से सक्षम शत्रु के साथ पूर्ण युद्ध में वे पूर्ण सुरक्षा नहीं दे सकती। (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

आरएएस मुख्य परीक्षा स्थगित करने की याचिका पर सुनवाई नहीं हुई

जयपुर, 16 जून। आरपीएससी की ओर से मंगलवार से शुरू होने वाली आरएएस मुख्य परीक्षा-2024 को हाईकोर्ट में याचिका दायर कर चुनौती दी गई। आकाश मिश्रा व दो अन्य ने याचिका दायर कर मुख्य परीक्षा को स्थगित करने की गुहार की है। याचिकाकर्ताओं ने अवकाशकालीन न्यायाधीश मनीष शर्मा के समक्ष प्रकरण की सुनवाई सोमवार को ही करने की गुहार की थी, लेकिन अदालत ने सुनवाई से इनकार कर दिया।

याचिका में अधिवक्ता तनवीर अहमद ने बताया कि आरपीएससी से 17 और 18 जुलाई को आरएएस भर्ती-

■ याचिका में कहा गया है कि 2023 की भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हुई। उसके पूरे होने तक 2024 की परीक्षा स्थगित की जाए।

2024 की मुख्य परीक्षा का आयोजन कर रही है, जबकि अभी तक आरएएस भर्ती-2023 की भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। वर्तमान में, इस परीक्षा के साक्षात्कार चल रहे हैं। ऐसे में, बीते साल की इस परीक्षा की प्रक्रिया पूरी होने तक आरएएस-2024 की मुख्य परीक्षा को स्थगित किया जाए।

याचिका में यह भी कहा गया कि प्रदेश के दोनों उपमुख्यमंत्री, एमशुएल और एमपी मुख्य परीक्षा को स्थगित करने की सिफारिश कर चुके हैं। इस आधार पर परीक्षा स्थगित होने के निर्णय की प्रतीक्षा (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

ट्रंप, इज़रायल-ईरान के बीच में भी युद्ध विराम कराने को लालायित

पर, ईरान कतर व ओमान को मध्यस्थ बनाना चाहता है

■ जैसा कि विदित है, ट्रंप ने दावा किया था कि उन्होंने भारत-पाकिस्तान के बीच ‘‘सौज़ाफायर’’ करवाया था।

■ सऊदी अरब भी परोक्ष रूप से मध्यस्थता के प्रयास में जुड़ना चाह रहा है।

■ ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने भी विदेशी राजदूतों से बातचीत करते हुए कहा कि ईरान ‘‘नेगोशिएटिंग टेबल’’ पर आकर, जैसा कि ट्रंप ने कहा है, अपनी न्यूक्लियर गतिविधियों पर नियंत्रण करने को तैयार हैं। मगर, अमेरिका को इज़रायल के हवाई हमलों को भी रोकना पड़ेगा।

करता हूँ, लेकिन मुझे कभी श्रेय नहीं मिलता, कोई बात नहीं, लोग तो समझते हैं। मिडिल ईस्ट को फिर से महान बनाएंगे।’’

इस बीच, जैसे ही इज़रायल ने ईरान पर अपने हमलों का दायरा बढ़ाया, तेहरान ने कतर और ओमान से राजनयिक माध्यमों के जरिए संपर्क किया है और क्षेत्रीय मध्यस्थों से हस्तक्षेप कर बातचीत फिर से शुरू करने का अनुरोध किया है। यह जानकारी रविवार को कई इज़रायली मीडिया संस्थानों ने

इज़रायली सरकारी सूत्रों के हवाले से दी है। उन्होंने इज़राइली सरकारी सूत्रों के अनुसार, ईरान ने कतर और ओमान से अमेरिका तक यह संदेश पहुंचाने को कहा है कि वह संघर्षविराम पर बातचीत के लिए तैयार है, या फिर अमेरिका इज़रायल को हमला रोकने के लिए कहे। वहीं, सऊदी अरब भी कथित तौर पर इस संघर्ष को शांत करने के लिए गुप्त कूटनीति में सक्रिय है।

ईरान के विदेश मंत्री अब्बास (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

सोनिया गांधी अस्पताल में भर्ती, हालत स्थिर

सोनिया गांधी को रविवार की रात पेट की तकलीफ के कारण सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती कराया गया था

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 16 जून। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को रविवार रात पेट संबंधी समस्या के चलते सर गंगा राम अस्पताल में भर्ती कराया गया था। सोमवार को उनकी स्थिति स्थिर बताई गई। डॉक्टरों की विशेष निगरानी में उनका इलाज चल रहा है और फिलहाल चिंता की कोई बात नहीं है। इससे पहले, उन्होंने शिमला में अपनी नियमित मैडिकल जाँच करवाई थी।

सर गंगा राम अस्पताल के चयरमैन डॉ. अजय स्वरूप ने इस बात की पुष्टि की तथा कहा, ‘‘श्रीमती सोनिया गांधी को रात 9:00 बजे सर्जिकल गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी विभाग में पेट की समस्या के कारण भर्ती किया गया। फिलहाल उनकी हालत स्थिर है और डॉक्टरों की टीम उनकी सावधानीपूर्वक निगरानी कर रही है।’’

अठहत्तर वर्षीय वरिष्ठ नेता

■ सर गंगाराम अस्पताल के चैंयरमैन डॉ. अजय स्वरूप ने कहा कि सोनिया गांधी को रात में सर्जिकल गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी विभाग में भर्ती कराया गया था। डॉक्टरर्स की टीम उनकी निगरानी कर रही है, फिलहाल उनकी हालत स्थिर है।

■ गत दिनों जब सोनिया गांधी शिमला में थीं तब भी उनकी तबियत कुछ बिगड़ गई थी और उन्हें जाँच के लिए शिमला के इंदिरा गांधी मैडिकल कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल ले जाया गया था, तब उनका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ पाया गया था।

सोनिया गांधी, जो अब भी कांग्रेस पार्टी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं, ने इससे पहले हिमाचल प्रदेश में चिकित्सीय सलाह ली थी। 7 जून को उन्हें मामूली अस्वस्थता के बाद शिमला के इंदिरा गांधी मैडिकल कॉलेज और अस्पताल (आईजीएमसी) ले जाया गया था, जहाँ उनका नियमित स्वास्थ्य परीक्षण किया गया।

मई में बेरोजगारी दर बढ़कर 5.6 प्रतिशत हुई

नयी दिल्ली, 16 जून। देश में मई 2025 में बेरोजगारी की दर बढ़ कर 5.6 प्रतिशत हो गयी है। केंद्रीय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय ने सोमवार को यहां जारी श्रम बल सर्वेक्षण - मई 2025 में कहा कि अप्रैल 2025 में बेरोजगारी की दर 5.1 प्रतिशत रही थी

■ सोमवार को जारी लेबर फोर्स सर्वे रिपोर्ट के अनुसार, अप्रैल में बेरोजगारी दर 5.1 प्रतिशत थी जो बढ़कर 5.6 प्रतिशत हो गई है।

जो मई में बढ़ कर 5.6 प्रतिशत हो गयी है।

मंत्रालय ने बताया कि संबंधित सर्वेक्षण में 15 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों को शामिल किया जाता है। मई 2025 के सर्वेक्षण के लिए 7511 गांवों और उप नगरों को शामिल किया गया। इसमें 89 हजार 372 परिवार रहे। कुल तीन लाख 79 हजार 600 लोगों से बात की गयी।

1,500 कश्मीरी विद्यार्थी तेहरान के ‘‘वॉर ज़ोन’’ में फंसे हुए है

ये विद्यार्थी, तेहरान में मैडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं, डॉक्टर बनने के लिए

■ भारत सरकार इन विद्यार्थियों की हिफाज़त व उन्हें वहाँ से सुरक्षित निकालने के लिए प्रयासरत है।

■ ईरान ने भी भारत सरकार को विश्वास दिलाया है कि ईरान भी पूरी तरह इसी कोशिश में लगा हुआ है कि कैसे इन विद्यार्थियों के लिए ‘‘सेफ पैसेज’’ की व्यवस्था करें, जिससे वे अपने देश पहुँच सकें।

अभिभावकों की ओर से भावनात्मक अपील की है और भारत सरकार से अनुरोध किया है कि वह राजनयिक प्रयास तेज करे और हर संभव कदम उठाए, ताकि फंसे हुये युवाओं की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने कहा, ‘‘सरकार को तुरंत सक्रिय हो जाना चाहिए ये छात्र घर से दूर, एक युद्ध क्षेत्र के बीच फंसे हुए हैं और उनकी सुरक्षा राष्ट्र की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए।’’

प्राप्त जानकारी के अनुसार, अधिकांश छात्र तेहरान के पास स्थित हुज्जत दोस्त अली छात्रावास में रह रहे हैं, छात्रावास ऐसे क्षेत्र के पास स्थित है,

जो सैन्य कार्यवाही तेज होने पर प्रभावित हो सकता है। चिकित्सा छात्रों के अलावा, कई कश्मीरी युवा उद्यमी और व्यापारी भी ईरान में हैं, जो विभिन्न व्यावसायिक और शैक्षणिक गतिविधियों में लगे हुए हैं। खासतौर से कश्मीर घाटी के श्रीनगर और अन्य हिस्सों में छात्र परिवारों में गहन चिंता का माहौल है। अभिभावक बता रहे हैं कि वे अपने बच्चों के साथ नियमित संपर्क में हैं, लेकिन संचार में बाधाएँ, आपूर्तियों की कमी, और हवाई हमलों की आशंका के चलते छात्रों का भय बढ़ता जा रहा है। श्रीनगर-निवासी एक अभिभावक मुश्ताक अहमद ने कहा, ‘‘हम हर दिन अपने बेटे

से बात करते हैं, लेकिन उसकी आवाज़ में डर बढ़ता जा रहा है। हम सरकार से अपील करते हैं, कृपया हमारे बच्चों को घर वापस लाएं।’’

विदेश मंत्रालय ने इस संकट को स्वीकार किया है और सूत्रों के अनुसार, एक आपातकालीन योजना पर काम किया जा रहा है, जिसमें वहाँ से निकलने के लिये सुरक्षित मार्गों की पहचान, आवश्यकता पड़ने पर भारतीय नागरिकों की एयरलिफ्टिंग, और क्षेत्र में सहयोगी देशों से समन्वय शामिल हैं। तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों तथा विद्यार्थियों के लिए एडवाइजरी भी जारी की है, जिसमें घर के अंदर रहने, भोड़-भाड़ वाले स्थानों से बचने, और दूतावास से लगातार संपर्क में रहने की सलाह दी गई है।

चूँकि भू-राजनीतिक स्थिति अस्थिर बनी हुई है, आने वाले दिन निकासी अभियानों के लिए निर्णायक होंगे। भारत की प्रतिक्रिया न केवल उसकी राजनयिक दक्षता की परीक्षा (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

प्र.मंत्री मोदी को मिला सायप्रस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान

निकोसिया, 16 जून। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को सोमवार को यहां साइप्रस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से अलंकृत किया गया। साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडौल्लिडेस ने राष्ट्रपति महल में प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया और द्विपक्षीय बैठक के बाद एक संक्षिप्त

■ सायप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडौल्लिडेस ने ‘‘द ग्रेट क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस-3’’ से मोदी को अलंकृत किया।

समारोह में साइप्रस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ‘दि ग्रेट क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस-3’ से अलंकृत किया।इस मौके पर मोदी ने कहा कि यह किसी नरेन्द्र मोदी का नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है और वह भारत के नागरिकों की ओर से पूरी विनम्रता से इस सम्मान को स्वीकार कर रहे हैं।

‘बार-बार निरुत्साहित करने के बावजूद वरिष्ठ अधिवक्ता क्यों ग्रीष्मावकाश में सुप्रीम कोर्ट पैरवी करने आते हैं?’

सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ अधिवक्ताओं के इस आचरण पर भृकुटि तानी व कटाक्ष किया

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 16 जून। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर वरिष्ठ अधिवक्ताओं से अपील की है कि वे गर्मी की छुट्टियों के दौरान कोर्ट में पेश न हों, ताकि युवा वकीलों को केस लड़ने का अधिक अवसर मिल सके। सोमवार को कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ताओं की उपस्थिति पर असंतोष जताया।

न्यायमूर्ति संदीप मेहता और न्यायमूर्ति प्रसन्ना बी वराले की अवकाश पीठ ने यह टिप्पणी उस समय की, जब वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी आज ऐमटैक समूह के प्रवर्तक अरविंद धाम की ओर से अदालत में उपस्थित हुये। धाम ने मनी लॉण्डरिंग केस में अन्तरिम जमानत दिये जाने का अनुरोध किया था।

कोर्ट ने सुनवाई के दौरान, इस प्रकरण में

■ सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि ग्रीष्मावकाश के दौरान जब कोई मुकदमा सुप्रीम कोर्ट की ‘‘वैकेशन बेंच’’ में लगता है, यह मौका होता है, युवा वकीलों, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड को बहस करने का, पर, वैकेशन बेंच के समक्ष अगर, फिर वरिष्ठ अधिवक्ता ही आते हैं तो वो युवा वकीलों का ‘‘मौका’’ छीनते हैं, जो उचित नहीं है।

■ वैकेशन बेंच ने सोमवार को यह टिप्पणी उस समय की, जब, मुकुल रोहतगी अपने क्लाइंट को जमानत दिलवाने के लिए बेंच के सम्मुख पेश हुए।

■ बेंच ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की तीन सदस्यीय बेंच जमानत के लिए दायर इस अर्ज़ी को पहले ही रद्द कर चुकी है। अतः, अब वरिष्ठ अधिवक्ता वैकेशन बेंच के समक्ष पुनः अपनी अर्ज़ी पेश कर रहे हैं, यह उचित नहीं है।

■ मुकुल रोहतगी ने अपनी जमानत की अर्ज़ी वापस लेने का प्रयास किया।

रोहतगी की उपस्थिति के सिलसिले में मौखिक रूप से कहा, ‘‘हमें समझ नहीं आता कि छुट्टियों में वरिष्ठ वकील क्यों पेश हो रहे हैं। इस कोर्ट ने पहले भी इस पर टिप्पणी की है।’’

यह पहला अवसर नहीं है, जब सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ वकीलों से अवकाश काल में मामलों

की बहस से दूर रहने की बात कही है।

जून 2023 में न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने यही कहा था कि ग्रीष्मकालीन छुट्टियों के दौरान, एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड या जूनियर वकीलों को अपने केस प्रस्तुत करने का, तथा उनमें बहस

करने का अवसर मिलना चाहिए।

मई 2024 में भी न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति संजय करोल की पीठ ने यही भावना दोहराई थी तथा कहा था कि वरिष्ठ वकीलों को कोर्ट के अवकाश के दौरान, बार के युवा सदस्यों को मुकदमों में बहस करने को

अवसर देना चाहिये। जस्टिस करोल ने उस समय कहा था, ‘‘हम चाहते हैं कि युवा बार आगे बढ़े, अवकाश का उद्देश्य भी यही था - युवा अधिवक्ताओं को मंच देना।’’

पिछले महीने भी न्यायमूर्ति बीबी नागरत्ना और न्यायमूर्ति एससी शर्मा की पीठ ने यही राय व्यक्त की थी कि वरिष्ठ वकीलों को गर्मियों की छुट्टियों में कोर्ट में होने वाली सुनवाईयों व बहस से दूर रहना चाहिए।

हालांकि सोमवार को कोर्ट ने वरिष्ठ अधिवक्ता रोहतगी की उपस्थिति पर सवाल उठाया और कहा कि वे कोर्ट के अवकाश के दौरान, केस में बहस करने क्यों आये हैं, लेकिन अंततः कोर्ट ने उनकी संक्षिप्त दलीलें सुन लीं। रोहतगी ने कहा कि उनके मुवक्किल पिछले 11 महीनों से हिरासत में हैं और उनकी नियमित जमानत याचिका फरवरी 2025 से दिल्ली (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

करोना संक्रमण से 11 मरीजों की मौत

नयी दिल्ली, 16 जून। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण से 11 और मरीजों की मौत होने से इस वायरस से मरने वालों की कुल संख्या 108 पहुँच गयी और 119 सक्रिय मामले घटने के साथ कुल सक्रिय मामले 7264 हो गये हैं। इससे

■ इसी बीच एक अच्छी खबर यह है कि कोरोना के एक्टिव केसों में मामूली गिरावट आई है। रविवार को कोरोना के एक्टिव केस 7383 थे जो सोमवार को घटकर 7264 रह गए।

पहले रविवार को कोरोना के एक्टिव केसों की कुल संख्या 7383 थी। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से आज जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में कोरोना के संक्रमण से केवल में सात, (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

‘प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन 10 दिसम्बर को आयोजित होगा

मुख्यमंत्री भजनलाल ने सम्मेलन की कार्ययोजना तैयार करने के लिए बैठक ली

जयपुर, 16 जून। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थानियों ने अपने सामर्थ्य की बदौलत विश्वभर में प्रदेश का मान बढ़ाया है। उन्होंने अपनी कर्मभूमि पर काम करते हुए मातृभूमि पर सामाजिक सरोकारों के कार्यों में पूर्ण रूप से समर्पित होकर कार्य किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रवासी राजस्थानियों के योगदान के सम्मान में राज्य सरकार आगामी 10 दिसम्बर को प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन का आयोजन करने जा रही है।

शर्मा सोमवार को मुख्यमंत्री निवास पर प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन-2025 की कार्ययोजना के संबंध में आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रवासी राजस्थानियों की सहूलियत और उनके मुद्दों के लिए राज्य सरकार एक नए विभाग का गठन करने जा रही है। साथ ही, सभी जिलों में अतिरिक्त जिला कलक्टर को प्रवासी राजस्थानियों से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए नोडल अधिकारी बनाने के संबंध में आदेश एवं गाइडलाइन भी जारी हो चुकी है।

शर्मा ने कहा कि “आपणो अग्रणी राजस्थान” के लक्ष्य की प्राप्ति के क्रम में, प्रदेश में निवेश बढ़ाने के लिए प्रवासी



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन-2025 की कार्ययोजना के संबंध में आयोजित बैठक को संबोधित किया। उन्होंने 10 दिसम्बर को होने वाले इस आयोजन को सफल बनाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिये।

- मुख्यमंत्री भजनलाल ने राजस्थान फाउन्डेशन के 14 नये चैप्टर्स की कार्यकारिणी का गठन कर सक्रिय लोगों को जोड़ने के निर्देश दिए। उन्होंने यह भी कहा कि फाउन्डेशन अपने विभिन्न चैप्टर्स की बैठक आयोजित कर नियमित संवाद करे।

राजस्थानियों का सहयोग लिया जाए।

नियमित संपर्क करें और उन्हें प्रदेश में निवेश के लिए प्रोत्साहित करें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान फाउन्डेशन के 14 नए चैप्टर्स के मनोनीत अध्यक्ष कार्यकारिणी के गठन की प्रक्रिया शीघ्र प्रारंभ कर सक्रिय लोगों को जोड़ें। फाउन्डेशन अपने विभिन्न चैप्टर्स की बैठक आयोजित कर निरंतर संवाद भी करें। बैठक में संबंधित विभागों के उच्च अधिकारीगण उपस्थित थे।

प्र.मंत्री मोदी आज कैनडा पहुंचेंगे

निकोसिया, 16 जून। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी साइप्रस की यात्रा पूरी करके आज शाम कैनडा के कैलगरी के लिए रवाना हो गये। मोदी ने लार्नाका अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरने के पहले एक्स पर साइप्रस के नेताओं के प्रति अभिप्रा व्यक्त किया।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर

- प्र.मंत्री कैलगरी में आयोजित हो रही जी-7 शिखर वार्ता में शिरकत करेंगे।

जायसवाल ने एक्स पर लिखा, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने साइप्रस की यादगार यात्रा पूरी की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलीड्स और साइप्रस के लोगों को उनकी असाधारण गर्मजोशी और आतिथ्य के लिए धन्यवाद दिया। जायसवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री जी-7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए कैनडा जा रहे हैं।

करोना संक्रमण ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

छत्तीसगढ़, दिल्ली, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में एक-एक मरीज की मौत हो गयी है। पिछले 24 घंटों में उत्तर प्रदेश, राजस्थान और कर्नाटक में जहां ज्यादा सक्रिय मामले सामने आये हैं वहीं राष्ट्रीय राजधानी, केरल, तमिलनाडु और गुजरात में सक्रिय मामलों में कमी आयी है। गत 22 मई को देश में कोरोना के सिरफ़ 25.7 एफ़्टिव थे जो आज बढ़ कर 7264 तक पहुंच गए। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक इस दौरान 13604 मरीज कोरोना के संक्रमण से ठीक हो गये हैं। पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के सबसे अधिक सक्रिय मामले उत्तर प्रदेश से 37, राजस्थान से 30 और कर्नाटक से 18 मामले सामने आये हैं और दिल्ली में 33, केरल में 87 और महाराष्ट्र में 38 मामले कम हुए हैं।

इज़रायल का “आयरन डोम” ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

भारत लंबे समय से इज़राइली रक्षा तकनीक को मजबूत, युद्ध-नरीक्षित और रणनीतिक रूप से विश्वसनीय मानता आया है। यह छवि अब भी काफी हद तक बरकरार है, लेकिन यह घटना स्पष्ट करती है कि कोई भी प्रणाली अचूक नहीं होती। किसी भी एक डिफेंस लेयर, चाहे वह इज़राइली हो, अमेरिकी हो, रूसी हो या स्वदेशी हो, पर अत्यधिक निर्भरता खतरनाक हो सकती है। भारत को इज़राइली मिसाइल रक्षा के अधिग्रहण को अब एक वास्तविक बहु-स्तरीय और अनकूलनशील रक्षा ढांचे के निर्माण की आवश्यकता के साथ संतुलित करना होगा।

यह घटना स्वदेशी अनुसंधान और विकास (जैसे डीआरडीओ की आकाश और क्यूआरएसएम प्रणालियाँ) की महत्ता और आयातित व स्वदेशी प्लेटफ़ार्मों के बीच तालमेल की जरूरत को भी रेखांकित करती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह भारत की अपनी कमजोरियों को भी उजागर करती है, विशेषकर इसके वायु सैन्य अड्डों, शहरी केन्द्रों और पश्चिमी व उत्तरी सीमाओं पर स्थित रणनीतिक

परिसंपत्तियों पर सैल्युरेशन हमलों के प्रति। भारत को भविष्य की प्रौद्योगिकी-आधारित प्रतिरोध क्षमताओं में भी निवेश करना होगा, जैसे उच्च-ऊर्जा लेजर, ड्रोन स्वार्म, एंसाई, संचालित हवाई क्षेत्र प्रबंधन, और इलेक्ट्रो मैगनेटिक युद्ध प्रणाली, जो पारंपरिक इंटरसेप्टर मिसाइलों को तुलना में अधिक तेजी से खतरों का जवाब दे सकती हैं।

इज़राइल-ईरान संघर्ष अब एक वेहद खतरनाक और अभूतपूर्व चरण में प्रवेश कर चुका है, जहाँ सीधे सैन्य हमले और लक्षित हत्यार्य सामने आ रही हैं, और यह इस क्षेत्र, और संभवतः विश्व, को एक बड़े संघर्ष की ओर ले जा सकता है।

13 जून 2025 को, इज़राइल ने “ऑपरेशन राइजिंग लायन” लॉन्च किया, यह एक व्यापक हवाई हमला था, जिसमें ईरान के भीतर 100 से अधिक ठिकानों को निशाना बनाया गया। इनमें नर्ताज जैसे परमाणु संवर्धन केन्द्र, भूमिगत सैन्य परिसर, और प्रमुख कमांड सेंटर शामिल थे। यह हमला केवल रणनीतिक नहीं, बल्कि व्यक्तिगत भी था। इस हमले में ईरान के शीर्ष सैन्य अधिकारी मारे गए, जैसे

आईआरजीसी कमांडर होसैन सलामी, सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ़ स्टाफ़ मेजर जनरल मोहम्मद बाघेरी, वरिष्ठ रणनीतिकार गोलांम अली राशिद, और कई परमाणु वैज्ञानिका ईरान ने इस हमले को राष्ट्रीय नायकों की सामूहिक हत्या बताया और कम से कम 78 लोगों की मौत तथा 320 से अधिक के घायल होने की पुष्टि की।

इसके जवाब में, ईरान ने मिसाइलों और ड्रोन से समन्वित हमला किया, जिसमें, कुछ रिपोर्टों के अनुसार, 100 से 200 प्रक्षेपास्त्र शामिल थे। इनके लक्ष्य थे, तेल अवीव और यरूशलेम जैसे शहरों का केन्द्र और प्रमुख रक्षा प्रतिष्ठान। यह जवाबी हमला इज़राइल की प्रसिद्ध आयरन डोम प्रणाली में एक बड़ी संध था। कई मिसाइलें इंटरसेप्ट से बच निकलीं और सीधे शहरी व सैन्य ठिकानों को भेद गईं, जिनमें किरिया कंपाउंड (जो इज़राइल का पेटांगन कहा जाता है) भी शामिल है।

इसका मनोवैज्ञानिक असर तात्कालिक था। इज़राइली शहरों में सायरन गूँज उठे, नागरिक बंकरों में भागे, और आयरन डोम की अजेयता का भ्रम चकनाचूर हो गया।

ट्रंप, इज़रायल...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

अरागजी ने भी, अपने एक कथन से इन राजनीतिक प्रयासों की पुष्टि की, जिसमें उन्होंने कहा कि ईरान अब भी परमाणु समझौते पर बातचीत के लिए तैयार है, यह ट्रंप के उस बयान का संभावित जवाब है जिसमें उन्होंने ईरान से परमाणु वार्ता की मेज पर लौटने को कहा था।

अरागजी ने तेहरान में विदेशी डिप्लोमेट्स से कहा, “हम किसी भी ऐसे समझौते के लिए तैयार हैं जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना हो कि ईरान परमाणु हथियार न बनाए।”

1,500 कश्मीरी ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

होगी, बल्कि वह भी साबित करेगी कि वह अपने नागरिकों, विशेष रूप से कश्मीर जैसे संवेदनशील क्षेत्रों के लोगों, की सुरक्षा को कितनी प्राथमिकता देता है।

सहायता के लिए, ईरान में मौजूद भारतीय नागरिक भारतीय दूतावास की 24x7 आपातकालीन हेल्पलाइन पर संपर्क कर सकते हैं, या, विदेशों में भारतीय नागरिकों के लिए आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से, अपनी स्थिति और संपर्क विवरण पंजीकृत कर सकते हैं।

हाँगकाँग से दिल्ली आ रहे ड्रीम लाइनर विमान में तकनीकी खराबी

नयी दिल्ली, 16 जून। अहमदाबाद लंदन एयर इंडिया विमान हादसे के चार दिन बाद हांगकाँग से दिल्ली आ रहे एयर इंडिया के एक और बोईंग 787-8 ड्रीमलाइनर विमान में उड़ान भरने के चंद मिनट बाद तकनीकी समस्या का पता लगने पर उसे वापस हांगकाँग लौटना पड़ा।

सूत्रों के अनुसार हांगकाँग से दिल्ली आने वाली एयर इंडिया की उड़ान एआई315 बीती रात 11 बज कर 59 मिनट पर हांगकाँग से रवाना हुई थी। रिकार्ड के अनुसार यह उड़ान तीन घंटे भी मिनट के विलंब से रवाना

- लगभग एक घंटे की उड़ान के बाद एयर इंडिया के इस विमान को पुन हाँगकाँग लौटाया गया, जहां उसकी जांच की जा रही है।

हुई थी। उड़ान भरने के बाद पायलट को हवा में ही तकनीकी समस्या का संदेह हुआ। इस पर पायलट ने विमान को समुद्र के ऊपर कुछ देर उड़ाया और जब दिक्कत दूर नहीं हुई तो वापस लौटने का फैसला किया।

इसके बाद विमान करीब एक घंटे 19 मिनट बाद अपने मूल स्थान यानी हांगकाँग हवाई अड्डे पर वापस लौट आया। विमान स्थानीय समयानुसार एक बज कर 18 मिनट पर हांगकाँग हवाई अड्डे पर उतरा। जहां उसकी गहन तकनीकी जांच की जा रही है।

‘बार-बार निरुत्साहित ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

हाईकोर्ट में विचाराधीन है। इसलिए उन्होंने उनके मुबिक्कल को अंतरिम जमानत देने की मांग की। इस पर कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इसी तरह की याचिका पहले ही सुप्रीम कोर्ट की तीन-न्यायाधीशों वाली पीठ द्वारा खारिज की जा चुकी है। जस्टिस मेहता ने कहा, “हम इस याचिका के पीछे की रणनीति तथा दलीलों से कतई प्रभावित नहीं हैं। आपकी एसएलपी इस कोर्ट के तीन जजों की बैच द्वारा पहले ही खारिज की जा चुकी है और अब आप अवकाश के दौरान एक बार खारिज किये जा चुके मामले में उसी राहत को फिर से पाने की कोशिश कर रहे हैं।” जब कोर्ट ने आदेश लिखवाना शुरू किया, तब रोहतगी ने याचिका वापस लेने की अनुमति माँगी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया और याचिका वापस ले ली गई।

जज की पोस्ट के लिए तीन साल लॉ प्रैक्टिस की अनिवार्यता के खिलाफ याचिका दर्ज

याचिका दायरकर्ता ने इस अनिवार्यता को अनुच्छेद 14 व 16 के तहत मूल अधिकारों का हनन बताया

- अधिवक्ता चंद्रसेन यादव ने याचिका दायर की और यह भी कहा कि तीन साल की अनिवार्यता महिलाओं, पहली पीढ़ी के वकीलों व आर्थिक रूप से कमजोर अभ्यर्थियों को हतोत्साहित कर सकती है।

नयी दिल्ली, 16 जून। सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के लिए तीन साल की वकालत अनिवार्य करने के उच्चतम न्यायालय के फैसले के खिलाफ समीक्षा याचिका दायर की गई है।

न्यायिक सेवा के इच्छुक याचिकाकर्ता अधिवक्ता चंद्रसेन यादव शीर्ष अदालत के 20 मई, 2025 के उस फैसले की समीक्षा की मांग की है, जिसमें सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के पद के लिए परीक्षा में बैठने के वास्ते बार में कम से कम तीन साल की प्रैक्टिस अनिवार्य की गई है।

शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में देश के सभी उच्च न्यायालयों और राज्य सरकारों को संबंधित सेवा नियमों में संशोधन करने का निर्देश दिया था, जिसके तहत सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के रूप में न्यायिक सेवाओं में शामिल होने इच्छुक अभ्यर्थियों को अब अधिवक्ता के रूप में तीन साल का अनुभव अनिवार्य करने का प्रावधान करने को कहा था।

समीक्षा याचिका में यादव ने तर्क दिया कि बार में तीन साल की प्रैक्टिस अनिवार्य करने की मनमानी और अनुचित शर्त लगाने के कारण संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के तहत उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है।

उन्होंने दलील दी कि न्यायाधीश पद पर नियुक्ति आवेदक के लिए नए प्रावधान के कारण उनके समान अवसर

अधिवक्ता कुनाल यादव के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया है कि तीन साल की अनिवार्य वकालत के नियम अभी नहीं, बल्कि उसे वर्ष 2027 से ही लागू किया जाना चाहिए। इससे हाल ही में विधि स्नातक हुए (2023-2025) विद्यार्थी अनुचित तौर पर प्रभावित नहीं होंगे, जिन्होंने पिछले पात्रता मानदंडों के अनुसार तैयारी की थी।

शीर्ष अदालत के फैसले पर याचिका में कहा गया, ऐसे नए विधि स्नातकों की संख्या या सफलता दर पर कोई विचार नहीं किया गया, जिन्होंने ऐतिहासिक रूप से न्यायिक सेवाओं में

अच्छा प्रदर्शन किया है और प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद न्यायपालिका में प्रभावी ढंग से काम किया है। ऐसे तथ्य के अभाव में, यह निर्णय (शीर्ष अदालत का) संवैधानिक आवश्यकता का उल्लंघन करता है।

याचिकाकर्ता ने यह भी तर्क दिया कि तीन साल की आवश्यकता महिलाओं, पहली पीढ़ी के वकीलों और आर्थिक रूप से कमजोर उम्मीदवारों को हतोत्साहित कर सकती है, जिनके पास स्थिर न्यायिक पद हासिल करने से पहले अनिश्चित वकालत (कानूनी अभ्यास) को बनाए रखने के साधन नहीं हो सकते हैं।

याचिका में कहा गया, न्यायालय को शेड्यूल आयोग की सिफारिशों की उचित रूप से सराहना करनी चाहिए थी, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया था कि यदि युवा और मेधावी विधि स्नातकों को गहन प्रशिक्षण दिया जाता है, तो न्यायिक सेवा में प्रवेश के लिए बार में तीन साल के अभ्यास को पूर्व शर्त के रूप में निर्धारित करना आवश्यक नहीं हो सकता है।

याचिका में यह भी तर्क दिया गया कि इस निर्णय ने विधि स्नातकों के एक पूरे वर्ग को पूरी तरह से अयोग्य घोषित कर दिया जबकि यह प्रमाणित नहीं किया गया कि तीन साल के अभ्यास के बिना प्रत्येक विधि स्नातक को न्यायिक सेवा में प्रवेश के आवेदन के लिए अयोग्य माना जाए।

आरएस मुख्य ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

की जा रही थी, पर परीक्षा स्थगित नहीं होने पर, अंतिम समय पर याचिका दायर की गई है। याचिका में यह भी कहा गया कि भारत-पाक के बीच टकराव के दौरान बॉर्डर एरिया में इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रभावित रही, लाइब्रेरी आदि को भी बंद कर दिया गया, जिससे अभ्यर्थी भी प्रभावित हुए। वहीं, एक्स सर्विसमें नेटों में आवेदन करने वाले कई अभ्यर्थियों को पुनः ड्यूटी पर बुलाया गया था। इस लिए उन्हें भी अध्ययन का मौका नहीं मिला। याचिका में कहा गया कि आरपीएससी पूर्व में भी कई बार मुख्य परीक्षा के स्थगित कर चुकी है। एक भर्ती में तो मुख्य परीक्षा की तिथि से दो दिन पूर्व ही भर्ती स्थगित की गई थी। ऐसे में अभ्यर्थियों के हितों को देखते हुए, मंगलवार से होने वाली मुख्य परीक्षा को स्थगित किया जाए। वहीं, दूसरी ओर अदालत ने आरएस भर्ती-2023 के साक्षात्कार में याचिकाकर्ता सुरेश मोणा को शामिल करने को कहा है।

सोनिया ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

इसी प्रकार आईजीएमजी के डिप्टी मैडिकल सुपरिंटेंडेंट डॉ. अमन चौहान ने भी आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा, “उनका ब्लड प्रेशर थोड़ा बढ़ा हुआ था, लेकिन कोई गंभीर बात नहीं थी। केवल सामान्य जाँचें की गईं तथा किसी विशेष जाँच या इलाज की आवश्यकता नहीं पड़ी।” हाल ही में, सोनिया गांधी के प्रायः अस्पताल जाने की खबरें देश भर में सुर्खियों में रही हैं, क्योंकि वे दशकों से भारतीय राजनीति का एक प्रमुख चेहरा रही हैं। हालांकि चिंता की कुछ खबरें सामने आईं, लेकिन दिल्ली और शिमला दोनों जगह से मिले चिकित्सकीय अपडेट यह दर्शाते हैं कि घबराने की कोई बात नहीं है।

सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करना हुआ अब और भी आसान...

आरबीआई रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप का उपयोग करके कभी भी, कहीं भी सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करें, जिनमें शामिल हैं

- ▶ खज़ाना बिल
- ▶ सावरेन स्वर्ण बॉण्ड
- ▶ अस्थिर दर बचत बॉण्ड 2020

आरबीआई रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप को डाउनलोड करने के लिए स्कैन करें

अधिक जानकारी के लिए, <https://rbiretaildirect.org.in> पर विजिट करें हमें यहाँ लिखें: support@rbiretaildirect.org.in

आरबीआई रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप के फायदे:

- सरकारी प्रतिभूति बाज़ार तक आसान पहुंच
- तुरंत लॉगइन, सरल यूजर इंटरफ़ेस और आसान नेविगेशन
- भुगतान के कई विकल्प - नेट बैंकिंग, UPI और NACH
- परिपक्वता पर गारंटीकृत लाभ, शून्य ब्रोकरेज और अन्य कोई शुल्क नहीं

जनहित में जारी **भारतीय रिज़र्व बैंक** **RESERVE BANK OF INDIA** www.rbi.org.in